भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 402 का उत्तर

देश में विशेषकर बिहार में नई और लंबित रेल परियोजनाएं

402. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सहित देश में नई और लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

देश में विशेषकर बिहार में नई और लंबित रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री देवेश चन्द्र ठाकुर के अतारांकित प्रश्न सं. 402 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल परियोजनाओं/सर्वेक्षणों को राज्य-वार/जिला-वार/क्षेत्र-वार/निर्वाचन क्षेत्र-वार स्वीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि जोन-वार स्वीकृत किया जाता है क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम स्थान संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक महत्व के आधार पर क्षेत्रीय रेल-वार शुरू किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफार्वर्ड और धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, बिहार सहित पूरे भारतीय रेल में, लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल अवसंरचना (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) परियोजनाएं योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर लिया गया है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। सारांश इस प्रकार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (किलोमीटर)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर)	मार्च 2024 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपए में)

नई लाइनें	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

सभी रेल परियोजनाओं का लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय रेल में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए परिव्यय का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹11,527 करोड़ प्रति वर्ष
2024-25	₹68,634 करोड़ (लगभग 6 गुना)

भारतीय रेल में नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण नीचे दिया गया है::-

अवधि	कमीशन किया गया नया रेलपथ	नये रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 किमी	4.2 किमी/दिन
2014-24	31,180 किमी	8.54 किमी/दिन (2 गुना से अधिक)

बिहार

बिहार राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल

परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली 5,064 कि.मी. कुल लंबाई वाली 79,356 करोड़ रुपये लागत की 55 परियोजनाएं (31 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 22 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिनमें से 1194 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर लिया गया है और मार्च, 2024 तक 26,983 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इसका सारांश इस प्रकार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर)	कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर)	मार्च 2024 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	31	2712	464	13629
आमान परिवर्तन	2	348	288	1520
दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग	22	2005	442	11834
कुल	55	5064	1194	26983

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	1,132 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	10,033 करोड़ रु. प्रति वर्ष (8 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली नई रेल पटरियों की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किया गया नया रेलपथ	नये रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	318 किमी	63.6 किमी प्रतिवर्ष
2014-24	1,669 किमी	166.9 किमी प्रतिवर्ष (लगभग 2.62 गुना)

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत भागीदारी को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में शामिल हैं (i) धन के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर

शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीवन संबंधी मंजूरी में तेजी लाने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

******